भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1757
03.08.2026 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय नीति के लिए डाटा प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण

1757 श्री रविचंद्र वद्दीराजू:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी की सटीकता में सुधार लाने के लिए कोई नए उपाय प्रारंभ किए हैं;

(ख) भारत की सांख्यिकीय प्रणालियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाए

गए हैं; और

(ग) क्या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी वास्तविक समय आधारित डिजिटल डैशबोर्डों के माध्यम से की जा रही है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधुनिकीकरण पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि कंप्यूटर-सहायक व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) जिसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को ई-सिग्मा प्लेटफ़ॉर्म, जो कि अंतर्निहित सत्यापन जांच, एआई-सक्षम चैटबॉट, बहुभाषी इंटरफ़ेस आदि शामिल हैं, के साथ एकीकृत किया गया है । एमओएसपीआई ने उच्च-आवृत्ति वाले सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की उभरती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्पकालिक सर्वेक्षण शुरू किए हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ सर्वेक्षणों के लिए प्रतिदर्श ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु प्रशासनिक डेटासेट एकीकृत किए गए हैं, जिससे सर्वेक्षण की दक्षता में सुधार हुआ और आधिकारिक सांख्यिकी के समय से संकलन में योगदान मिला।

समष्टिगत आर्थिक सांख्यिकी में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार संशोधन शामिल हैं।

एमओएसपीआई ने व्यापक डेटा समन्वय/मानकीकरण पहलें की हैं, जिनमें ,अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना (एनएमडीएस 2.0) को अपनाना, सांख्यिकीय गुणवत्ता मूल्यांकन रूपरेखा (एसक्यूएएफ) की शुरूआत, और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण मानकों के साथ संरेखण शामिल हैं।

(ख) एमओएसपीआई वैश्विक सांख्यिकीय मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों की भारतीय संदर्भ में उपयुक्तता तथा भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली में संभावित अंगीकरण/अनुकूलन की समीक्षा करता है, साथ ही सांख्यिकीय आंकड़ों की सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार के उपाय भी करता है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मई 2016 में संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक सांख्यिकी के मूलभूत सिद्धांतों (यूएनएफपीओएस) को अपनाना शामिल है, ताकि देश में आधिकारिक सांख्यिकी के उत्पादन और प्रसार में अच्छी पद्धतियों और पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सके। अन्य पहलों में नए आधार वर्ष 2024 (पहले का आधार वर्ष 2012 था) के साथ दिनांक 12.02.2026 को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की नई श्रृंखला में उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग का वर्गीकरण (सीओआईसीओपी) – 2018 रूपरेखा को अपनाना तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2025 को सभी आर्थिक कार्यकलापों के अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (आईएसआईसी) संशोधन 5 के अनुरूप जारी करना शामिल है। एमओएसपीआई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप, व्यापक डेटा समन्वय/मानकीकरण पहलें भी की हैं, जिनमें ,अन्य बातों के साथ-साथ, सांख्यिकीय गुणवत्ता मूल्यांकन रूपरेखा (एसक्यूएएफ) की शुरूआत शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखा (यूएन एनक्यूएएफ) 2019 पर आधारित है और अधिक दक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही लाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। राष्ट्रीय लेखों की अंतर्निहित अवधारणाएँ और कार्यप्रणाली संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, 2008 के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीआई और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष डेटा प्रसारण मानकों (एसडीडीएस) का पालन करते हैं।

एमओएसपीआई ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संकेतक रूपरेखा (जीआईएफ) के साथ घनिष्ठ संरेखण में सतत विकास लक्ष्य – राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एसडीजी-एनआईएफ) भी विकसित की है। यद्यपि यह ढाँचा जीआईएफ पर आधारित है, तथापि एनआईएफ में संकेतकों को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, नीतिगत परिप्रेक्ष्यों तथा आँकड़ा-पारितंत्र (डेटा इकोसिस्टम) के अनुरूप अनुकूलित किया गया है।

(ग) एमओएसपीआई ने केंद्रीय क्षेत्र के अवसंरचना परियोजनाओं की अनिवार्य निगरानी के लिए पैमाना (प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन-बिल्डिंग) को कार्यान्वित किया है, जो पूर्ववर्ती ओसीएमएस-2006 (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली) को प्रतिस्थापित करता है। अवसंरचना निगरानी के प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिए, एमओएसपीआई ने एक कार्य-निष्पादन निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो मानकीकृत संकेतकों के एक सेट के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। 16 अप्रैल, 2026 को प्रमुख अवसंरचना उप-क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन का व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए अवसंरचना निगरानी और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करने हेतु डैशबोर्ड लॉन्च किया गया।

*****